RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : • Email : garvigujarat2007@gmail.comgarvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 341 | दि. 12-04-2019 शुक्रवार | वि.सं. 2075 | चैत्र सुद-०७ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

बिहार के भागलपुर में एक चुनावी रैली में बोले पीएम नरेन्द्र मोदी

सरकार दोबारा आई तो टुकड़े-टुकड़े गैंग टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर जाएगा

नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षाबलों को खुली छूट दे दी है : महामिलावटी लोग देश में भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं : नरेन्द्र मोदी

(संपूर्ण समाचार सेवा)भागलपुर, लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को बिहार के भागलपुर में एक चुनावी रैली में पीएम नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। इस दौरान पीएम ने यह भी दावा किया कि २३ मई को देश में मोदी की सरकार दोबारा बननी तय है। साथ ही पीएम ने वादा किया कि उनकी सरकार नक्सलवाद और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेगी। पीएम ने कहा कि उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षाबलों को खुली छूट दे दी है। इस दौरान विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दोबारा आई तो टुकड़े-टुकड़े गैंग टुकड़े- टुकड़े होकर बिखर जाएगा। भागलपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा, ये महामिलावटी लोग देश में भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे जवानों को निहत्था और असहाय बनाना चाहते हैं। ये महामिलावटी नेता डर फैला रहे हैं कि अगर इस बार फिर मोदी आ गया तो देश में चुनाव ही खत्म हो जाएगा। ये यह भी डर फैला रहे हैं कि मोदी फिर सत्ता में आ गया तो संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। दरअसल, ये इसलिए इस भ्रम को फैला रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि मोदी फिर आएगा तो इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएंगी। इनकी वंशवादी राजनीति के दिन लद जाएंगे। रक्षा सौदों की दलाली बंद हो जाएगी। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए पीएम ने कहा, २०१४ के पहले का भारत याद कीजिए। तब पाकिस्तान आतंकियों को भेजता था और बाद में धमकी भी देता था। कांग्रेस की सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाती थी। पर, हमने उनके घर में घुसकर मारा। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में घूमकर रोना रो रहा है लेकिन उसे कोई घास तक नहीं डाल रहा। पीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, एक तरफ हम कह रहे हैं जम्मू-कश्मीर में भी आतंक के अड्डों का पता लगा देंगे। पाक से पैसा लेने वाले को जेल में डालेंगे। उधर, कांग्रेस और उसके साथी कह रहे हैं कि आतंकवाद पर पाक से बात की जाएगी। जो पाक से पैसा लेते हैं उन पर कोई भरोसा कर सकता है क्या। दरअसल, ये खुद डरे हुए हैं। अविश्वास से गिरे हुए हैं। इस देश को उनसे अब सीधा जवाब चाहिए कि वे देश के जवानों के साथ हैं या आतंकियों के साथ हैं। इस दौरान पीएम ने केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले ७० सालों में जो चीजें नामुमकिन थीं, हमने उन सबको मुमकिन कर दिखाया है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा, आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वह सिर्फ आपके आशीर्वाद और सहयोग से संभव हुआ है। देश को मजबूत करने और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आगे भी आपके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है।

असम के मंगलदोई में कांग्रेस पर मोदी का बड़ा हमला

लोग 'तुगलक रोड चुनावी घोटाले' की चर्चा कर रहे हैं

एक तरफ ये लोग चौकीदार को चोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी लूट का पर्दाफाश हो रहा है : नरेन्द्र मोदी

(संपूर्ण समाचईार सेवा) मंगलदोई (असम), पीएम मोदी ने गुरुवार को असम के मंगलदोई में कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने हाल ही में एमपी और दिल्ली में आयकर विभाग के छापों का जिक्र कर कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर चुनाव लड़ रही है। पीएम ने कहा आजकल देश में 'तुगलक रोड चुनावी घोटाले' की चर्चा है। पीएम ने कहा, कांग्रेस का एक नया घोटाला सामने आया है, जिसका नाम है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। दिल्ली में तुगलक रोड पर एक बंगले में एक बड़े कांग्रेसी नेता का घर है। इस बंगले से बीते कुछ दिनों से सैकड़ों करोड़ रुपये का खेल खेला गया है। पीएम ने कहा, इस बंगले से जिन लोगों के तार जुड़े हैं, उनके पास से बोरे भर के नोट मिले हैं। एक तरफ ये लोग चौकीदार को चोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी लूट का पर्दाफाश हो रहा है। यह पैसा गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने भेजा था। गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर नामदारों की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे लोगों को वोट देकर भी पाप लगेगा। पीएम ने कहा कि झूठ और फरेब के हथियार लेकर चौकीदार को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपका वोट सीधे मोदी के खाते में जाएगा। पीएम ने अपने कामों का जिक्र कर कहा कि आपके वोट ने असम के डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों बैंकों में खाते खुलवाए हैं। आपके वोट ने गरीब महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। आपके वोट ने २४ किसानों के खाते में हर साल १५०० करोड़ रुपये जमा कराने का काम किया है। पीएम ने कहा कि आपका वोट तय करेगा कि हम डर कर रहें या अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। आतंकवाद से समझौता नहीं हो सकता, नक्सलवाद से समझौता नहीं हो सकता। हमारे विरोधी दल भारत को कमजोर नीति पर चलाना चाहते हैं। गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर नामदारों की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे लोगों को वोट देकर भी पाप लगेगा। पीएम ने कहा कि झूठ और फरेब के हथियार लेकर चौकीदार को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपका वोट सीधे मोदी के खाते में जाएगा। पीएम ने अपने कामों का जिक्र कर कहा कि आपके वोट ने असम के डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों बैंकों में खाते खुलवाए हैं। आपके वोट ने गरीब महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। आपके वोट ने २४ किसानों के खाते में हर साल १५०० करोड़ रुपये जमा कराने का काम किया है। पीएम ने कहा कि आपका वोट तय करेगा कि हम डर कर रहें या अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मोदी ने कहा, असम में घुसपैठ होती रही और कांग्रेस उसका फायदा उठाती रही। कांग्रेस चाहती तो असम से जम्मू-कश्मीर तक समस्याएं खत्म हो सकती थी। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हमारी सरकार ने ही किया है। घुसपैठियों को बाहर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। असम समझौते को कांग्रेस ने ३ दशक तक लटकाकर रखा। ब्रह्मपुत्र पर कई साल से बन रहे पुल को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पांच पुल बनाने का फैसला लिया है, जिन्हें जल्द ही बना लिया जाएगा।

कांग्रेस ने युपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया

राहुल की सुरक्षा में हुई चूक, गृह मंत्रालय को लिखा पत्र

कांग्रेस के दावे के मुताबिक, कम से कम ७ बार राहुल गांधी पर ग्रीन कलर की लेजर लाइट दिखाई दी

(संपूर्ण समाचार सेवा)नई दिल्ली, कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव का पर्चा भरने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का दावा किया गया है। कांग्रेस ने खुद इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी है और दावा किया है कि अमेठी में पर्चा भरने के दौरान राहुल पर हमले की तैयारी थी। केंद्र को लिखे गए पत्र में कांग्रेस ने सभी तरह के राजनीतिक मतभेद किनारे रखकर उनकी सुरक्षा को प्रमुख बताया है। पत्र में राहुल के पिता और दादी पर हुए हमलों का भी जिक्र किया गया है। इस चूक के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी १० अप्रैल यानी बुधवार को अमेठी गए थे। वहां उनके साथ सोनिया गांधी के साथ-साथ पूरा वाड्रा परिवार भी था। नामांकन भरने के बाद राहुल ने मीडिया से बात की थी। उसी दौरान का एक विडियो कांग्रेस द्वारा दिखाया गया है और मंत्रालय को भी भेजा गया है। कांग्रेस के दावे के मुताबिक, विडियो में दिख रहा है कि कम से कम ७ बार राहुल गांधी पर ग्रीन कलर की लेजर लाइट दिखाई दी। कांग्रेस ने खुद इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी है और दावा किया है कि अमेठी में पर्चा भरने के दौरान राहुल पर हमले की तैयारी थी। केंद्र को लिखे गए पत्र में कांग्रेस ने सभी तरह के राजनीतिक मतभेद किनारे रखकर उनकी सुरक्षा को प्रमुख बताया है। पत्र में राहुल के पिता और दादी पर हुए हमलों का भी जिक्र किया गया है। इस चूक के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।उनमें से कुछ बार वह उनकी कनपटी के आसपास देखी गई थी। कांग्रेस की तरफ से यह पत्र सीनियर नेता अहमद पटेल, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला ने भेजा है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल की जान को खतरा है। पत्र में लिखा गया है कि इस तरह साजिश करके देश के दो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को मारा गया उसने पूरे देश को हिला दिया था। पत्र में आगे लिखा गया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई इस चूक की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। पत्र में आगे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

रायबरेली लोकसभा सीट से पांचवीं बार नामांकन

सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट से नामांकन दाखिल किया

सोनिया ने मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि २००४ मत भूलिए : वाजपेयी भी अजेय थे लेकिन हम जीते

(संपूर्ण समाचार सेवा)रायबरेली, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से पांचवीं बार नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि २००४ मत भूलिए। उन्होंने यह भी कहा, वाजपेयी भी अजेय थे लेकिन हम जीते। बता दें कि २००४ में सभी सियासी पंडितों के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सोनिया के साथ राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में एक बार फिर पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा, भारतीय इतिहास में ऐसे कई लोग रह हैं जो यह सोचते थे कि वह अजेय हैं और भारत के लोगों से बड़े हैं। नरेन्द्र मोदी ने ५ साल में भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वह बस इतना बता दें कि उन्होंने अनिल अंबानी को ठेका कैसे दिया ? सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चार बाद सांसद रह चुकी हैं। पर्चा दाखिल करने से पहले सोनिया गांधी ने हवन और फिर रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा रॉबर्ट वाड्रा, रेहान और मिराया वाड्रा भी मौजूद रहे। रायबरेली सीट गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रही है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कर्मभूमि मानी जाती है। नामांकन दाखिल करने से पहले सोनिया ने गांधी परिवार के गुरुजी गयाप्रसाद शुक्ल के आवास पर लाभ मुहूर्त में हवन भी किया। २००४ में सभी सियासी पंडितों के दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सोनिया के साथ राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में एक बार फिर पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा, भारतीय इतिहास में ऐसे कई लोग रह हैं जो यह सोचते थे कि वह अजेय हैं और भारत के लोगों से बड़े हैं। नरेन्द्र मोदी ने ५ साल में भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वह बस इतना बता दें कि उन्होंने अनिल अंबानी को ठेका कैसे दिया ? सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चार बाद सांसद रह चुकी हैं। पर्चा दाखिल करने से पहले सोनिया गांधी ने हवन और फिर रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा रॉबर्ट वाड्रा, रेहान और मिराया वाड्रा भी मौजूद रहे। रायबरेली सीट गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रही है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कर्मभूमि मानी जाती है। खराब स्वास्थ्य के चलते सोनिया गांधी ने खुले ट्रक के बजाय गाड़ी से रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीच-बीच में बाहर निकालकर कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ भी हिलाया। रोड शो के दौरान सड़कों पर कांग्रेस समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ आया। लोग हाथों में कांग्रेस के झंडे के साथ, न्याय योजना के प्रचार की टीशर्ट और राफेल के लिए काले झंडे भी लिए हुए थे। लगभग ७०० मीटर के रास्ते पर रोड शो करते हुए सोनिया गांधी कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन पर्चा भरा। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए मतदान पांचवें चरण के तहत छह मई को होगा। इस बार सोनिया का मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह से है, जो कांग्रेस छोडकर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। एसपी और बीएसपी ने रायबरेली से उम्मीदवार नहीं उतारा है। सोनिया इस सीट पर २००४, २००६ (उपचुनाव), २००९ और २०१४ में विजयी रही हैं।

राजनीति का मकसद जनसेवा-समर्पण

मेरी मां से हर राजनेता को सीखना चाहिए : प्रियंका

(संपूर्ण समाचार सेवा)रायबरेली, अमेठी में बुधवार को राहुल गांधी के नामांकन के बाद गुरुवार यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के रायबरेली से पर्चा दाखिल करने और रोड शो के दौरान समूचा गांधी और वाड्रा परिवार एक साथ नजर आया। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा रॉबर्ट वाड्रा, रेहान और मिराया वाड्रा भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी के नामांकन के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हर राजनेता को उनकी मां से सीख लेनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, रायबरेली की जनता के प्रति मेरी मां की श्रद्धा से हर प्रत्याशी और हर राजनेता को सीखना चाहिए। राजनीति का मकसद जनसेवा और समर्पण है। जिसे भी यह मौका मिलता है उसे जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए।

जूलियन असांजे को पुलिस ने लंदन से किया गिरफ्तार

(संपूर्ण समाचार सेवा)लंदन, विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन अंसाजे को लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास से अरेस्ट कर लिया गया है। बीते ७ सालों से असांजे ने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले रखी थी। एक यौन उत्पीड़न के केस में स्वीडन में प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए असांजे ने दूतावास को अपना ठिकाना बना रखा था। लंदन की मेट्रोपोलिटन पुलिस ने कहा कि फिलहाल असांजे को हिरासत में लिया गया है और उन्हें वेस्टमिन्सटर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि असांज ने २०१० में बड़ी संख्या में अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था। असांजे ने स्वीडन में प्रत्यर्पण से बचने के लिए २०१२ में इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। बाद में स्वीडन ने असांजे पर से सेक्स अपराध से जुड़े मामले को हटा दिया। इसके बावजूद असांजे दूतावास में ही बने रहे क्योंकि जमानत का मामला खत्म हो जाने की वजह से लंदन में उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही थी। बीते साल १२ दिसंबर से उन्हें इक्वाडोर की नागरिकता मिली।

संपादकिय

कुछ राजनीतिक दलों ने झूठ का सहारा लेकर राफेल को चुनावी मुद्दा बना लिया

राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से मोदी सरकार के मन मुताबिक नहीं है, लेकिन इस फैसले का वह भी मतलब नहीं है जो कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के नेताओं की ओर से पेश किया जा रहा है। चूंकि चुनावी माहौल में राजनीतिक दल हर छोटे–ब ? मसले को तूल देते हैं इसलिए इस पर हैरत नहीं कि कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को अपनी जीत बताने में जुट गए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को क्लीन चिट दी थी तो कांग्रेस ने उस पर गौर करने से इन्कार करते हुए चौकीदार को चोर बताने का सिलसिला कायम रखा था। तब उसका यह भी तर्क था कि हम तो सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं थे और हमारी मांग यह है कि संयुक्त संसदीय समिति से इस सौदे की जांच हो। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई होनी ही थी। इन याचिकाओं की सुनवाई को लेकर सरकार ने यह दलील दी थी कि चोरी से हासिल किए गए दस्तावेजों का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक कमजोर दलील थी और उसके खारिज होने के आसार थे, लेकिन यह समझना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने में इतना वक्त क्यों लग गया कि किसी मामले की सुनवाई में चोरी से हासिल किए गए दस्तावेजों का संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं ? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि विशेषाधिकार वाले और साथ ही गोपनीयता अधिनियम के दायरे में आने वाले दस्तावेजों को किसी मामले की सुनवाई का हिस्सा बनाया जा सकता है तब फिर जरूरी यह है कि वह अपना अंतिम फैसला यथाशीघ्र दे। इसका कोई औचित्य नहीं कि राष्ट्रीय महत्व के एक जरूरी सौदे की सुनवाई लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में अटकी रहे। यह ठीक नहीं कि अभी भी यह तय नहीं कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कब से शुरू होगी ? इस मामले में अंतिम फैसला देने में इसलिए देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल राफेल सौदे में ग ?ब ?ी को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन यह विचित्र है कि उसके नेता न्यायाधीश की तरह व्यवहार करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, वे झूठ का भी सहारा ले रहे हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई को लेकर सरकार ने यह दलील दी थी कि चोरी से हासिल किए गए दस्तावेजों का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक कमजोर दलील थी और उसके खारिज होने के आसार थे, लेकिन यह समझना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने में इतना वक्त क्यों लग गया उनकी मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि वायुसेना की 30 हजार करो ? की राशि अनिल अंबानी को दी गई। आखिर यह कोरा झूठ नहीं तो क्या है ? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल सौदे पर प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती भी दे रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रहे कि क्या वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीद और नेशनल हेराल्ड मामले पर भी बहस करने को तैयार हैं ? जो भी हो, अगर राहुल गांधी के पास राफेल सौदे में ग ?ब ?ी का वैसा कोई सुबूत है जैसे बोफोर्स तोप सौदे या फिर अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में सामने आए थे तो फिर वे सार्वजनिक किए जाने चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने चाहिए।

1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोपा

(जी.एन.एस.) जब यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात को देखते हुए राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अपने राफेल राग पर लगाम लगाएंगे तब उन्होंने एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर 'चौकीदार चोर' का अपना नारा उछाला। इतना ही नहीं उन्होंने तथ्यों से मुंह चुराते हुए इस सौदे में देरी का आरोप भी मोदी सरकार पर म ? दिया, जबकि हर कोई जानता है कि मनमोहन सरकार कैसे वायुसेना की जरूरतों की अनदेखी कर कुंडली मारे बैठी रही। आखिर राहुल का रवैया खुद को जबरन सही साबित करने वाला नहीं तो और क्या है ? यह तो कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता है। राफेल पर पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राय को हिकारत भरी नजरों से देखना भला और क्या है ? इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने यही सब तो किया था! 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इंदिरा गांधी में यह प्रवृत्ति बलवती होने लगी थी। तब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इंदिरा गांधी एकाधिकारवाद की ओर बढ रही हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का नारा तो आपातकाल से पहले ही दे दिया गया था। इस नारे को कांग्रेसी सांसद शशि भूषण ने उछाला था। कांग्रेस नेतृत्व ने उसका कभी विरोध नहीं किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब ?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती

थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल ख ?ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। यानी एक ही तरह के आरोप से घिरे व्यक्ति को कांग्रेस कैग बनाए तो ठीक, पर यदि दूसरे दल की सरकार बना दे तो गलत। यही है कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता! यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि शर्मा या महर्षि के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे या सही। यहां तो सिर्फ दोहरे मापदंड की बात हो रही है। इस पृष्ठभूमि में यह बताना प्रासंगिक है कि कैग जैसी संस्था को हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी अधिक गरिमा प्रदान की और साथ ही प्रथम प्रधानमंत्री ने किस तरह उसका पालन किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब ?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल खडा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। सरकार के अफसर तो प्रधानमंत्री के मातहत होते हैं, पर कांग्रेस की मौजूदा पीडी ने राजनीतिक कारणों से संस्था के प्रति जवाहरलाल नेहरू की भावना की भी परवाह नहीं की। उसे तो बस यही चाहिए कि कोई संस्था उस व्यक्ति को राफेल मामले में दोषी ठहरा दे जिसको कांग्रेस दोषी देखना चाहती है। तभी उसे कांग्रेस के उस प्रथम परिवार के समकक्ष में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने मौजूदा प्रधानमंत्री को ला देने में सुविधा होगी। याद रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के प्रथम परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदार के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कैग की रिपोर्ट के बाद अच्छा होता कि राहुल राफेल पर दोबारा चर्चा करने से बचते। बहरहाल आपातकाल तथा अन्य अनेक कारणों से इंदिरा गांधी की 1977 के चुनाव में पराजय हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। तब लगा था कि कांग्रेस की इमरजेंसी की मानसिकता का खात्मा हो गया, पर कांग्रेस की नई पीडी तो उसे बनाए रखने के पक्ष में लगती है!

अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया

(जी.एन.एस.) आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सियोल यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी जीवनशैली जलवायु परिवर्तन के बडे कारणों में से एक है। यह बात शत–प्रतिशत सही है कि हमने जिस तरह की जीवनशैली अपना रखी है वह एक दिन हम सबको डुबो देगी या फिर हमारा दम घोंट देगी। अगर हम मात्र जीवन की कुछ बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित होते तो भी चलता, पर अत्यधिक पाने की लालसा हमारे लिए एक बडे संकट को जन्म दे रही है। दुर्भाग्य यह है कि हम इस बदलते हालात की चर्चा तो कर रहे हैं, पर इन सुविधाओं को त्यागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हर मौसम के बदले से तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं मिली थी ? जॉन टेंडल ने वर्ष 1850 में यह बता दिया था कि ग्रीन हाउस गैसें भीषण गर्मी या ठंडी का कारण बन सकती हैं। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक

परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमशः 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं जो कार्बन उत्सर्जन के खतरे को कम कर सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमने अपने उपयोगों के लिए भयानक रूप से जंगलों का हनन किया है। वर्ष 2017 में अकेले 390 लाख एकड वनों की कटाई हुई। मतलब एक मिनट में एक पेड काटा गया। यह कटाई हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रही है जिसके विकल्प खोजे जा सकते हैं। मसलन टिंबर के लिए 37 फीसद वनों का हनन होता है, वहीं खेती के लिए 28 फीसद, सडक निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में करीब 140 फीसद। इसके अतिरिक्त 21 फीसद वन दावानल की भेंट चड जाते हैं। यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि मीट और मीट उत्पाद से जुडी हमारी खाद्य आदतें भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बडा कारण हैं। दुर्भाग्य यह भी है कि इनके लिए वर्ष 2030 में आज के मुकाबले 67 फीसद ज्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग होगा। मतलब साफ है आने वाले दिनों में ये इंसानों में संक्रमण का एक बडा कारण बनेंगे। एक आकलन है कि वर्ष 2050 तक सालाना 9.5 मिलियन लोग इसका शिकार बनेंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन, निर्माण कार्य एवं कंप्यूटर डाटा जो आज मात्र एक फीसद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण हैं, वर्ष 2040 तक ये 14 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने लगेंगे। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमशः 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं यह इसलिए है, क्योंकि हम एक भोगवादी सभ्यता का बडा हिस्सा बन गए हैं। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमें यहां प्रकृति और विज्ञान के नियमों को समझने का समय है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। अब जो चर्चा का सबसे बडा विषय होना चाहिए वह यह कि हम अपनी जीवनशैली को ढेर सारी सुविधाओं के दृष्टिकोण से न देखें। संसाधनों का आवश्यकता एवं सुविधा भर उपयोग एक तरफ जहां हमें लंबा जीवन दे सकता है वहीं प्रकृति और पृथ्वी को भी विचलित नहीं करेगा। यह पूरी तरह सच है कि हमारी तेजी से बदलती हुई जीवनशैली ने हमें ऐसे मो ? पर पहुंचा दिया है जहां से आगे जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीने के तौर–तरीकों में सुविधाओं से ज्यादा साधनों के उन तरीकों को अपनाएं जो सततता प्रदान कर सकते हैं।

तापी जिले के सोनगढ़ में बोले नरेन्द्र मोदी

देश में दो पीएम न सरदार साहब को मंजूर थे न हमें

सरदार साहब ने जो रास्ता दिखाया था उसे अपनाया होता तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता : नरेन्द्र मोदी

(संपूर्ण समाचार सेवा) सोनगढ़,

बुधवार को दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल तापी जिले के सोनगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कांग्रेस पर हमले से की। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस की नीति की आलोचना करते हुए मोदी बोले, कश्मीर के एक नेता कहते हैं देश में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, यह बात आपको भी मंजूर नहीं और सरदार साहब को भी मंजूर नहीं थी। आज हालत यह है कि कश्मीर में जवानों का बलिदान नित्य क्रम बन गया है। अपने भाषण की शुरूआत में मोदी ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा, दक्षिण गुजरात में आकर सरदार साहब की याद आती है। सरदार साहब ने जो रास्ता दिखाया था उसे अपनाया होता तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने उसे छोड़ दिया। सरदार पटेल की नीति का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, सरदार पटेल के कारण हम जूनागढ़ का गुजरात में विलय करा पाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के विषय को अपने पास रखा, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र को फिर से ढकोसला पत्र बताते हुए मोदी ने कहा, अगर आज सरदार पटेल होते तो वो कांग्रेस के ढकोसला पत्र को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। मोदी ने कहा, कांग्रेस मोदी हटाने की बात करती है और मोदी गरीबी हटाने की बात करता है। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस की नीति की आलोचना करते हुए मोदी बोले, कश्मीर के एक नेता कहते हैं देश में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, यह बात आपको भी मंजूर नहीं और सरदार साहब को भी मंजूर नहीं थी। आज हालत यह है कि कश्मीर में जवानों का बलिदान नित्य क्रम बन गया है। अपने भाषण की शुरूआत में मोदी ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा, दक्षिण गुजरात में आकर सरदार साहब की याद आती है। सरदार साहब ने जो रास्ता दिखाया था उसे अपनाया होता तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने उसे छोड़ दिया।मोदी ने सरदार पटेल की विचाराधार और कांग्रेस की नीतियों में अंतर दिखाकर कांग्रेस की जमकर आलोचना की। मध्य प्रदेश में हाल ही में आयकर विभाग के छापों का जिक्र करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के घोटालों में एक नया घोटाला सबूतों के साथ और जुड़ गया है। वह है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। और देश ये भी जानता है कि तुगलक रोड पर कौन रहता है। आयुष्मान भारत योजना को अपनी उपलब्धि बताते हुए मोदी ने कहा, हम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना को देश के मध्यम और गरीब परिवारों तक ले आए। इस योजना से देश के ५० करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

सरखेज सहित के क्षेत्रों में एस्टेट विभाग की कार्रवाई

फायर सेफ्टी बिना चलते १० से ज्यादा ऑयल के गोदाम सील

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

अहमदाबाद शहर में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर फायरब्रिगेड सील लगाने की शुरूआत की हो ऐसा लगता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को फायरब्रिगेड द्वारा हाइराइज इमारत में चेकिंग शुरू किया गया है। जिसमें फायर सेफ्टी के साधन चालू नहीं हो या एनओसी नहीं हो ऐसी बहुमंजिला इमारतों और इकाई को नोटिस भेजना शुरू किया गया है। दूसरी तरफ, एएमसी प्रशासन के दक्षिण पश्चिम जोन के एस्टेट विभाग द्वारा सरखेज सहित के क्षेत्रों में अचानक सरप्राइज चेकिंग शुरू किया गया और फायर सेफ्टी की सुविधा बिना चलते ऑयल के १० से ज्यादा गोदाम तुरंत सील किए गए। गर्मी के यह दिनों में फायर सेफ्टी की सुविधा बिना इस प्रकार के इकाई की वजह से आग, दुर्घटना सहित की कोई दुर्घटना नहीं हो इस उद्देश्य से एएमसी प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की है। फायर विभाग द्वारा जिस बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी या एनओसी नहीं हो ऐसी इमारतों को भेजे गये नोटिस में हालांकि, कितने दिन में इसे लागू करके फायर सेफ्टी और एनओसी प्राप्त कर ले इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जिस पर से एक बात स्पष्ट होता है कि फायरब्रिगेड सिर्फ कामकाज दिखाने के लिए नोटिस दे रही है। नोटिस बाद भी फायर सेफ्टी के साधन चालू नहीं हो तो सील लगाना है कि नहीं इस निर्णय का आधार म्युनिसिपल कमिशनर विजय नेहरा पर रहेगा। यहां उल्लेखनीय है कि, शहर में बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी की सुविधा, एनओसी सहित के पूरे मामले में म्युनिसिपल कमिशनर विजय नेहरा बहुत ही गंभीर और स्पष्ट कार्यान्वयन नहीं मानने होने से फायरब्रिगेड विभाग भी सक्रिय हो गया है। गत दिन सीजी रोड पर सहित के छह अलग-अलग कॉम्पलेक्स में जांच करते सूर्यरथ, व्हाइट हाउस, सेंटर पोइन्ट और शिती रतन में फायर सेफ्टी के साधन चालू नहीं होने से उनको बुधवार को नोटिस भेजा गया। बाकी के दो कॉम्पलेक्स में फायर सेफ्टी के साधन चालू थे।

अभिनेता चंकी पांडे की पार्टी में दिखे

ब्लू आउटफिट में दिखे अर्जुन-मलाइका अरोड़ा

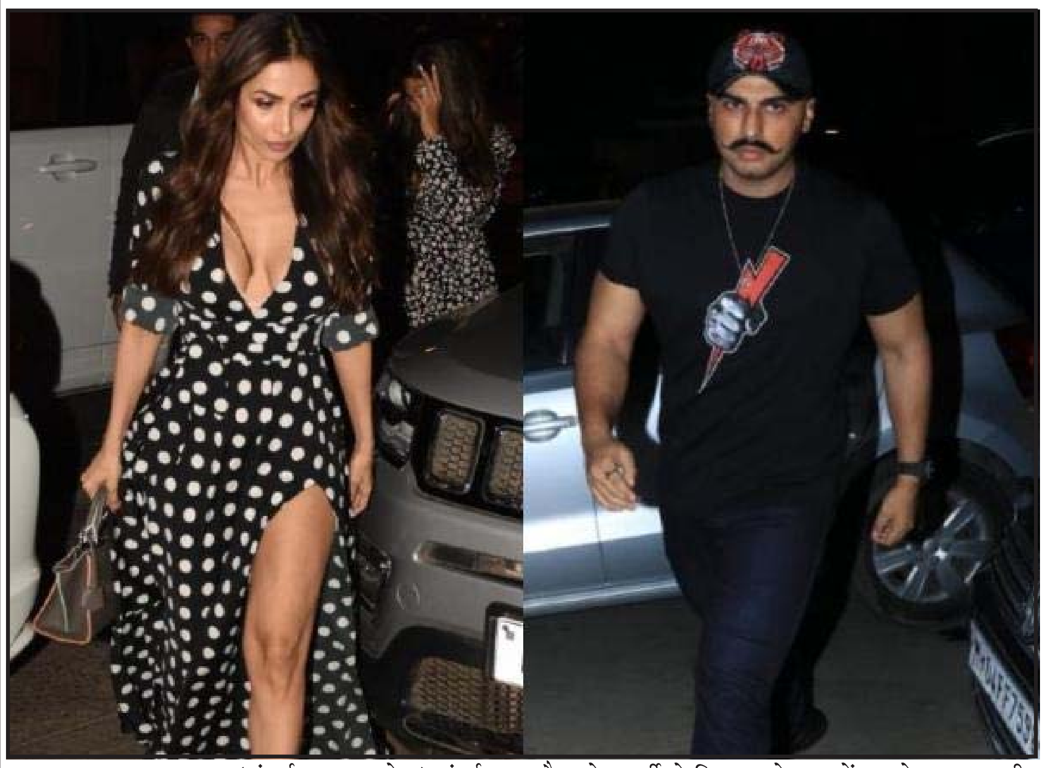

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

ऐसा लग रहा है कि लवबर्ड्स मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अपने रिलेशनशिप को एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैंप दोनों बीती रात चंकी पांडे की पार्टी में साथ-साथ पहुंचे। मलाइका और अर्जुन ने इस पार्टी में केवल साथ में एंट्री ही नहीं मारी, बल्कि दोनों सेम कलर के कपड़ों में भी दिखे जी हां, दोनों स्टार्स ब्लू कलर के कपड़ों में इस पार्टी में पहुंचे। दोनों मालदीव वकेशन से लौटने के बाद पहली बार साथ नजर आए। बता दें कि पिछले कुछ समय से दोनों की शादी को लेकर काफी चर्चा है और इसी बीच दोनों हाल ही में मालदीव छुट्टियां मनाने पहुंचेप मलाइका ने इस हॉलिडे की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह बिकीनी में नजर आ रही हैंप वकेशन से लौटने के बाद अर्जुन ने भी मालदीव हॉलिडे की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिससे साफ हो गया कि दोनों वहां साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि दोनों बैचलरेट पार्टी के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मालदीव पहुंचे थेप हालांकि, इसे लेकर किसी तरह का ऑफिशल कन्फर्मेशन जारी नहीं किया गया था। मलाइका और अर्जुन ने इस पार्टी में केवल साथ में एंट्री ही नहीं मारी, बल्कि दोनों सेम कलर के कपड़ों में भी दिखे जी हां, दोनों स्टार्स ब्लू कलर के कपड़ों में इस पार्टी में पहुंचे। दोनों मालदीव वकेशन से लौटने के बाद पहली बार साथ नजर आए। बता दें कि पिछले कुछ समय से दोनों की शादी को लेकर काफी चर्चा है और इसी बीच दोनों हाल ही में मालदीव छुट्टियां मनाने पहुंचेप मलाइका ने इस हॉलिडे की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह बिकीनी में नजर आ रही हैंप वकेशन से लौटने के बाद अर्जुन ने भी मालदीव हॉलिडे की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिससे साफ हो गया कि दोनों वहां साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे थे।आपको यह भी बता दें कि शादी के सवाल पर जहां अर्जुन के पिता बोनी कपूर इसे गलत करार दे चुके हैं, वहीं मलाइका भी शादी की खबरों को महज अफवाह बता चुकी हैं।

पिछले कुछ समय से दोनों की शादी को लेकर चर्चा है

अभियान के तहत वाहनों पर कलेक्टर ने स्टीकर लगाये

हमेशा मतदान अभियान का खुद कलेक्टर ने प्रारंभ कराया

प्रशासन द्वारा अहमदाबाद जिले में पांच लाख वाहनों पर मतदान जागरूकता लाने स्टीकर लगाने का आयोजन

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

अहमदाबाद शहर-जिले में अंतिम मतदाता सूची के अनुसार कुल ५४,९५,८५९ मतदाता पंजीकृत है। जिसमें १८-१९ वर्ष के कुल १,०१,२२७ मतदाता यह लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। जिसमें घाटलोडिया में सबसे ज्यादा ३,७६,१५९ मतदाता तो बापूनगर में सबसे कम १,९४,७२३ मतदाता पंजीकृत है। इस दौरान जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे द्वारा बुधवार से मतदान जागरूकता अभियान के तहत वाहनों पर स्टीकर लगाये गये और यह अभियान का प्रारंभ कराया गया। अहमदाबाद जिला कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे ने सभी नागरिकों को हमेशा अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अनुरोध किया और प्रजातंत्र में मतदान की ड्यूटी इस मौके पर समझाया। लोकसभा की आगामी २३ अप्रैल को आयोजित होने वाली चुनाव को अब कुछ ही दिन बाकी रहे है तब जिला कलेक्टर ने अपने पावर से जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे द्वारा मतदाताओं में मतदान जागरूकता लाने के लिए शहर-जिले की स्कूल-कॉलेजों, स्वैच्छिक संस्थाएं सहित कई स्थलों पर चुनाव में हमेशा मतदान के लिए जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। मतदान जन जागृति कार्यक्रम के तहत बुधवार को सुबह में जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे द्वारा शाहीबाग के डफनाला चार रास्ते के पास वाहनों पर स्टीकर लगाने का अभियान शुरू किया गया। इस दौरान जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे द्वारा बुधवार से मतदान जागरूकता अभियान के तहत वाहनों पर स्टीकर लगाये गये और यह अभियान का प्रारंभ कराया गया। अहमदाबाद जिला कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे ने सभी नागरिकों को हमेशा अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अनुरोध किया और प्रजातंत्र में मतदान की ड्यूटी इस मौके पर समझाया। लोकसभा की आगामी २३ अप्रैल को आयोजित होने वाली चुनाव को अब कुछ ही दिन बाकी रहे है तब जिला कलेक्टर ने अपने पावर से जिला चुनाव अधिकारी डॉ. विक्रांत पांडे द्वारा मतदाताओं में मतदान जागरूकता लाने के लिए शहर-जिले की स्कूल-कॉलेजों, स्वैच्छिक संस्थाएं सहित कई स्थलों पर चुनाव में हमेशा मतदान के लिए जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।जिला चुनाव प्रशासन द्वारा अहमदाबाद के एक भी मतदाता वंचित नही रहे यह नारे के तहत मतदान करने का प्रतीक प्रदर्शित करता स्याही की बूंद और नीचे सुगम निर्वाचन-२०१९ गुजरात तथा २३ अप्रैल, २०१९ मंगलवार को मतदान दिवस प्रदर्शित करती जानकारी वाली स्टीकर तैयार किया गया है। जिला चुनाव प्रशासन द्वारा अहमदाबाद जिले में पांच लाख जितने वाहनों पर मतदान जागरूकता लाने के लिए स्टीकर लगाने का आयोजन है।

पालड़ी चार रास्ते के पास विद्यार्थीयों के द्वारा सो फिसदी वोटींग के लिए प्रचार किया गया था।
(संपूर्ण समाचार सेवा)

कांग्रेस के सभी पद और सदस्य पद से इस्तीफा

अल्पेश ठाकोर ने आखिर में कांग्रेस से इस्तीफा दिया

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

पिछले कई समय से कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकोर के पार्टी बदलने के मामले में चर्चा चल रही थी लेकिन कई नाटक और विवाद बाद आखिर में अल्पेश ठाकोर ने बुधवार को कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। अल्पेश ने कांग्रेस के सभी पद और सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले अल्पेश ने कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को झटका लगा है लेकिन दूसरी तरफ, अल्पेश के भाजपा में शामिल होने को लेकर अभी भी प्रश्नचिह्न है। क्योंकि, खुद भाजपा के ठाकोर सीनियरों ने अल्पेश को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। अल्पेश ठाकोर ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपने सभी पद से इस्तीफा भेज दिया है। अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस में हमेशा उनको नजरअंदाज और अपमान की वजह से इस्तीफा दिए जाने का दावा किया है और इसके साथ इसके लिए ठाकोर सेना और समाज उत्तम होने का बताया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के समय अल्पेश ठाकोर के इस्तीफे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हालांकि भाजपा में शामिल होंगे कि नहीं यह मामले में प्रश्नचिह्न है। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार अल्पेश के भाजपा के साथ हुए सौदे के अनुसार, अल्पेश के साथी विधायकों में भरतजी ठाकोर, चंदनजी ठाकोर और गेनीबहन ठाकोर ने कांग्रेस छोड़ने तैयार नहीं होने पर अल्पेश की बाजी फ्लोप हो गई है। जबकि अल्पेश के साथ फिलहाल सिर्फ एक विधायक धवलसिंह झाला है। यदि अल्पेश ठाकोर कांग्रेस छोड़ देने के बाद अब भाजपा में इसे एंट्री मिलती है कि नहीं यह एक सवाल है। अल्पेश ठाकोर के इस्तीफे पहले लगाये जा रहे कयास मामले में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने बताया कि, अल्पेश ठाकोर भाजपा के संपर्क में नहीं है। जबकि ठाकोर सेना में भी अल्पेश ठाकोर के खिलाफ विरोध का माहौल पैदा होने पर अल्पेश का राजनीतिक करियर अब सवालों में घिर चुका है। कांग्रेस के विधायक अल्पेश सभी पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे ऐसी अटकलों के बीच इसके साथीदार धवलसिंह ने इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे लेकिन भरतजी और अल्पेश के साथ मिलकर कोई अंतिम निर्णय लेंगे।

ट्रक ने टेम्पो ट्रेक्स को जोरदार टक्कर मारने पर सात की मौत

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

सूरत शहर के वेसु क्षेत्र में स्थित नंदीनी-३ सोसाइटी में रहती महिलाओं की टेम्पो ट्रेक्सन ने नवसारी के पास दुर्घटना होने पर सात लोगों की मौत हो गई थी। यह महिलाएं वराछा की टेम्पो ट्रेक्सन को किराये पर लेकर दहाणुं महालक्ष्मीमाता के दर्शन करने गई थी, वहां से वापस आते समय यह गंभीर दुर्घटना हुई थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि, टेम्पो ट्रेक्स में पंक्चर होने की वजह से रोड के बगल में खड़ी रख दी गई थी और इसमें सवार यात्री भी नीचे उतरकर साइड में खड़े थे फिर भी एकदम स्पीड से आ रही ट्रक के चालक ने मोटी ट्रक यह सभी को कुचल देने से दुर्घटना हुई थी। एक दिन की यात्रा में दो व्यक्ति के जन्म दिन होने से गत दिन टेम्पो ट्रेक्स में जश्न मनाया गया लेकिन जन्म दिन का जश्न शोक में तब्दील हो गया। यह दुर्घटना को देखने वाली हंसाबहन ने फुलवाला बताई कि, नंदीनी श्रीसोसाइटी में रहती महिलाओं ने दहाणुं महालक्ष्मी माता के दर्शन करने का आयोजन किया था। गत दिन सुबह में ५ बजे सोसाइटी के सभी लोग नीचे जमा हुए। टेम्पो ट्रेक्स की पूजा करके ४५ से ५० दर्शनार्थी बैठे थे और सूरत से सीधा दहाणुं चले गये थे। जहां महालक्ष्मी माता के दर्शन किया। इस दौरान मेरा और रमणभाई का जन्म दिन होने से टेम्पो ट्रेक्स में ही जन्म दिन मनाया गया। डांस करके मस्ती के साथ जन्म दिन को मनाया गया। उन्होंने आगे बताया कि, रमणभाई के बेटे की शादी में हम लोगों को नहीं बुलाया था। जिसकी वजह से होटल में सभी लोगों को खाना खिलाया था। इसके बाद तीथल सांईबाबा के दर्शन करके राबडा विश्वंभरी माता के दर्शन करने गये।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने स्वागत किया

राफेल घोटाला मोदी सरकार का बड़ा रक्षा घोटाला : कांग्रेस

मोदी सरकार ने जनता को झूठे वादे किए इसके अलावा कुछ नहीं किया : जनता पहचान गई है : मनीष दोशी

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल केस में रिव्यू पीटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई करने का निर्णय किया है। तीनों न्यायाधीशों ने एक मत से दिए निर्णय में कहा कि नया दस्तावेज डोमेन में आया है, इसके आधार पर केस में रिव्यू पीटिशन पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पीटिशन पर सुनवाई के लिए नई तारीख निश्चित करेगी। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एसके. कौल और जस्टिस केएम. जोसेफ शामिल है। हालांकि, राफेल केस में सुनवाई करने के सुप्रीम कोर्ट के महत्व के फैसले को गुजरात कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मुद्दे पर ही दस्तावेज पेश किया गया था इसे जांच करके फिर सुनवाई करने का आदेश दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। वास्तव में, राफेल मोदी सरकार का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। इस दौरान कांग्रेस के युवा विधायक अल्पेश ठाकोर के इस्तीफे की संभावना के मामले में डॉ. मनीष दोशी ने कहा कि, सामाजिक संगठन को अपनी कौन-सी बात करना इसके लिए स्वतंत्र है, कांग्रेस अल्पेश ठाकोर सहित सभी को सम्मान देते है, हमारे प्रभारी ने अल्पेश ठाकोर के साथ बात की है, इस मामले में हमारा नेतृत्व उनके साथ बातचीत करेगा। अल्पेश के इस्तीफे की बात हमारे ध्यान पर नहीं आयी है। अल्पेश ठाकोर के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व खुले मन के साथ बातचीत कर रहा है।कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र प्रक्रिया है। वहीं कांग्रेस टूट रही है यह मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के निवेदन मामले में डॉ. मनीष दोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, गुजरात में सबसे ज्यादा घोटाला में डूबी रुपाणी सरकार है। कांग्रेस में क्या हो रहा है इसकी अपेक्षा भाजपा अपना ध्यान रखे। भाजपा में जगह-जगह बगावत हो रही है। भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं का अशांति है। जूनागढ़ में नरेन्द्र मोदी के निवेदन मामले में डॉ. मनीष दोशी ने बताया है कि, प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा नहीं बचाते है।

ईलेकशन कमिशन द्वारा शाहीबाद डफनाला के पास सो फीसदी वोटिंग के लिए स्टीकर लगाकर प्रचार किया गया था।
(संपूर्ण समाचार सेवा)

चुनावी रथ पर योगी सहित कई बड़े नेता सवार थे

स्मृति इरानी ने अमेठी सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया

स्मृति इरानी ने चार किमी लंबा रोड शो करके गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में ताकत का अहसास कराया

(संपूर्ण समाचार सेवा)अमेठी ,

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति इरानी ने गुरुवार को विशाल रोड शो के साथ अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन यात्रा में स्मृति इरानी के साथ चुनावी रथ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई बड़े नेता सवार थे। स्मृति इरानी ने चार किमी लंबा रोड शो करके गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में अपनी ताकत का अहसास कराया। इससे पहले उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बुधवार को तीन किमी लंबा रोड शो करते हुए पर्चा दाखिल किया था। रोड शो के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अमेठी की जनता रोशनी बिखेरने, अमेठी पर छाया अंधेरा मिटाने और वंशवाद का सूरज अस्त करने के लिए स्मृति इरानी को चुनकर नई विकास गाथा लिखेगी। स्मृति इरानी ने अपने घर की तरह ही अमेठी की देखभाल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में ७४ से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बता दें कि स्मृति इरानी को पहले अपना नामांकन पत्र १७ अप्रैल को दाखिल करना था लेकिन उस दिन छुट्टी होने के कारण उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल किया। अमेठी में पांचवें चरण में छह मई को मतदान होना है। स्मृति इरानी का अमेठी सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सीधा मुकाबला है। राहुल ने बुधवार को ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले २०१४ के लोकसभा चुनाव में स्मृति को राहुल गांधी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। विश्लेषकों के मुताबिक पिछले पांच साल में स्मृति इरानी ने काफी मेहनत की और इस बार राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देने के मूड में हैं। पर्चा दाखिल करने से पहले स्मृति इरानी ने अपने पति जुबिन इरानी के साथ पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। राहुल के नामांकन के दिन स्मृति इरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। स्मृति ने कहा,देश को खंडित करने और समाज को विखंडित करने का सपना देखने वालों को अपना समर्थन ना दें। इससे देश कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे अमेठी ने एक प्रत्याशी नहीं बल्कि दीदी के रूप में सम्मान दिया है। मैं अमेठी की सेवा अपना परम धर्म समझती हूं।

नागपुर के पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची ज्योति

सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने डाला वोट

मतदान के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए ज्योति ने कहा, मैं सभी लोगों से वोट डालने का आग्रह करती हूं

(संपूर्ण समाचार सेवा)नागपुर,

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच नागपुर के पोलिंग बूथ पर उस वक्त मतदाता से लेकर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हैरान रह गए, जब दुनिया की सबसे छोटी महिला यहां वोट डालने के लिए पहुंची। गिनेस बुक वर्ल्ड रेकॉर्ड धारक ज्योति आमगे ने गुरुवार को यहां के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज्योति की लंबाई महज ६३ सेंटीमीटर है। वोट डालने गईं ज्योति को लोग अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। लाल और चेक स्लीवलेस ड्रेस पहनीं दो फीट एक इंच की लंबाई वाली ज्योति अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए धैर्य के साथ कतार में खड़ी हुईं। मतदान के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए ज्योति ने मीडिया से कहा, मैं सभी लोगों से वोट डालने का आग्रह करती हूं। कृपया पहले वोट डालें फिर अपने अन्य काम करें। आमगे ने मतदान केंद्र संख्या- २५३ पर अपना वोट डाला। इस दौरान उस वक्त दिलचस्प नजारा दिखा, जब कागजी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए उन्हें मतदान कर्मी की टेबल पर खड़ा होना पड़ा। एक सिलेब्रिटी कुक और उद्यमी आमगे टीवी शो बिग बॉस-६ में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वह अमेरिकी और इटैलियन टीवी सीरीज में भी अभिनय कर चुकी हैं। लोनावाला (पुणे) के सिलेब्रिटी वैक्स म्यूजियम में उनका अपना स्टैचू भी लगा है। बता दें कि नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से कांग्रेस ने उनके खिलाफ नाना पटोले को उतारा है।

झड़प में टीडीपी नेता एस भास्कर रेड्डी की मौत

आंध्र में मतदान के दौरान भिड़े YSRC और TDP कार्यकर्ता

आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कोडेला शिवप्रसाद राव समेत १० लोग घायल हुए : कई जगहों पर टकराव

(संपूर्ण समाचार सेवा)हैदराबाद,

आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के लिए जारी पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगह से झड़प और मारपीट की सूचनाएं सामने आई हैं। अनंतपुर के ताडीपत्री में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में टीडीपी नेता एस. भास्कर रेड्डी की मौत हो गई। वहीं आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कोडेला शिवप्रसाद राव समेत १० लोग घायल हो गए। उधर, टीडीपी का आरोप है कि वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं ने भास्कर रेड्डी की हत्या की है। आंध्र में वहीं कई जगहों पर टकराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि अनंतपुर जिला के तदिपत्री वधानसभा क्षेत्र में टीडीपी कार्यकर्ता सिद्धा भास्कर रेड्डी पर विपक्षी वाईएसआरसीपी ने कथित रूप से हमला कर उनकी हत्या कर दी। रेड्डी देवापुरम गांव में मतदान केंद्र पर हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वहीं गुंटूर और प्रकाशम जिलों समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर दोनों पार्टियों के बीच हिंसा की खबरें आई हैं। इधर, बंदरापल्ली के पुथालापट्टू में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं में झड़प का एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल विडियो में दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। कुछ लोग विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे भड़का रहे हैं। इस बीच कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, जो पत्थर उठाकर भीड़ की तरफ फेंकती हैं। इस बीच कुछ और लोग उग्र हो जाते हैं और झड़प और बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि भीड़ को उग्र होता देख यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा उधर, अनंतपुर जिले के गुंताकल विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब जन सेना पार्टी के कैंडिडेट मधुसूदन गुप्ता ने ईवीएम उठाकर फर्श पर पटक दी। मधूसूदन गुप्ता गुत्ती के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाटने के लिए पहुंचे थे। आंध्र में वहीं कई जगहों पर टकराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि अनंतपुर जिला के तदिपत्री वधानसभा क्षेत्र में टीडीपी कार्यकर्ता सिद्धा भास्कर रेड्डी पर विपक्षी वाईएसआरसीपी ने कथित रूप से हमला कर उनकी हत्या कर दी। रेड्डी देवापुरम गांव में मतदान केंद्र पर हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वहीं गुंटूर और प्रकाशम जिलों समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर दोनों पार्टियों के बीच हिंसा की खबरें आई हैं। इधर, बंदरापल्ली के पुथालापट्टू में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं में झड़प का एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल विडियो में दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। कुछ लोग विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे भड़का रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह इस बात से नाराज थे कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के नाम सही तरीके से नहीं प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसको लेकर वह मतदान कर्मियों पर बरस पड़े। टना की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी मधुसूदन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने पुलिस के साथ भी बदसलूकी की।

मोदी खिलाफ की शिकायत से राजनीति गर्मा गई

मोढवाडिया की मोदी के खिलाफ आचारसंहिता भंग की शिकायत

आचारसंहिता के भंग करने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चुनाव आयोग के समक्ष मांग

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

लोकसभा चुनाव के लिए ११ अप्रैल को पहले चरण की कुल ९१ सीट के लिए उत्साह के माहौल में मतदान आयोजित किया जा रहा है। कुल सात चरण में मतदान आयोजित होने की वजह से गर्मी के साथ-साथ चुनावी माहौल की गर्मी तथा उत्तेजना में वृद्धि होती जा रही है। चुनाव प्रचार में जाने-अनजाने हुई गलती को लेकर उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के खिलाफ चुनाव आचारसंहिता भंग की शिकायतें भी दर्ज की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचारसंहिता भंग की शिकायत दर्ज कराने पर गुजरात लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा गई है।नये-नये आरोप और प्रत्यारोप और विवाद उठाये जा रहे होने से गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फर्स्ट वोटर को की गई अपील के मामले में चुनाव आचारसंहिता भंग की केंद्रीय चुनाव आयोग को गत दिन शिकायत करने पर यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने गत ९ अप्रैल को महाराष्ट्र के लातुर में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए फर्स्ट वोटर को अपील करते हुए कहा कि आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले जवानों को समर्पित हो सकता है? कुल सात चरण में मतदान आयोजित होने की वजह से गर्मी के साथ-साथ चुनावी माहौल की गर्मी तथा उत्तेजना में वृद्धि होती जा रही है। चुनाव प्रचार में जाने-अनजाने हुई गलती को लेकर उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के खिलाफ चुनाव आचारसंहिता भंग की शिकायतें भी दर्ज की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचारसंहिता भंग की शिकायत दर्ज कराने पर गुजरात लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा गई है।नये-नये आरोप और प्रत्यारोप और विवाद उठाये जा रहे होने से गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फर्स्ट वोटर को की गई अपील के मामले में चुनाव आचारसंहिता भंग की केंद्रीय चुनाव आयोग को गत दिन शिकायत करने पर यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है।क्या आपका पहला वोट पुलवामा जो वीर जवान शहीद हुए है यह वीर शहीदों के नाम पर समर्पित हो सकता है अर्जुन मोढवाडिया ने केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव की आदर्श आचारसंहिता के भंग के तौर पर यह अपील को बताकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में मोढवाडिया ने आचारसंहिता भंग करने पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चुनाव आयोग के समक्ष मांग की है। इस दौरान आज मोढवाडिया ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि, प्रधानमंत्री और भाजपा ने २०१४ पाकिस्तान के नाम का उपयोग किया था और फिर से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा है।

आगामी अक्टूबर महीने से कार्यान्वयन की संभावना

देश में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक एकसमान होगा

केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्रालय की तरफ से अध्यादेश जारी : गुजरात सरकार को भी लागू करने की सूचना

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

आगामी १ अक्टूबर से राज्यभर में अब वाहन रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस एकसमान होगा। इतना ही नहीं, लेकिन कार्ड या आधारकार्ड के जैसे देशभर में आरसी बुक और लाइसेंस एकसमान होगा। केंद्रीय मार्ग परिवहन विभाग द्वारा इस मामले में अध्यादेश जारी किया गया है। गुजरात सरकार को भी इस मामले में लागू करने की सूचना दी गई है। देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक में एक समानता लाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। फिलहाल में हरएक राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक अलग-अलग आकार-रंग और डिजाइन वाले है। नई व्यवस्था केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार १ अक्टूबर से लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार हरएक राज्य में एक ही समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक बनेगा। इसी वजह से आगामी समय में नये वाहनों की ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक नया रंग और आकार-डिजाइन की देखने को मिलेगी। नई आरसी बुक में वाहन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जानकारी प्रदर्शित होगी। मालिक का नाम-पता, नंबर और चेसीस नंबर प्रदर्शित किया गया होगा। पीछे की ओर इमरजन्सी मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित किया गया होगा। जबकि लाइसेंस में आगे की ओर फोटो की जगह, बगल में नाम-पता, जन्म तारीख और ब्लड ग्रुप लिखा होगा, ओर्गन डोनर है कि नहीं यह प्रदर्शित किया गया होगा। केंद्रीय मार्ग परिवहन विभाग द्वारा इस मामले में अध्यादेश जारी किया गया है। गुजरात सरकार को भी इस मामले में लागू करने की सूचना दी गई है। देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक में एक समानता लाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। फिलहाल में हरएक राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक अलग-अलग आकार-रंग और डिजाइन वाले है। नई व्यवस्था केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार १ अक्टूबर से लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार हरएक राज्य में एक ही समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक बनेगा। इसी वजह से आगामी समय में नये वाहनों की ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक नया रंग और आकार-डिजाइन की देखने को मिलेगी। कार्ड के पीछे क्यूआर कोड बताया जाएगा जो स्केन करते ही लाइसेंसधारक की सभी जानकारी मिल जाएगी, पहली बार लाइसेंस कब इश्यू हुआ इसकी जानकारी भी होगी। लाइसेंस की तय सीमा और अन्य जानकारी लिखी होगी तथा इमरजन्सी मोबाइल नंबर लिखा होगा।

लिस्ट तैयार की जा रही है, जहां प्रियंका प्रचार करेंगी

प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के बाहर करेंगी १०० रैलियां

प्रियंका गाधी कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रैलियां कर सकती हैं

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

हाल ही में यूपी में जोरदार चुनाव प्रचार और रोड शो करने वाली कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी अपने प्रचार अभियान का दायरा बढ़ाकर दूसरे राज्यों में भी रैलियां करेंगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि देश के उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है, जहां प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। एक कांग्रेसी नेता ने बताया, जमीनी रिपोर्ट के आधार पर लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें उन सीटों पर फोकस किया गया है, जहां कांग्रेसी उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत है और उन्हें थोड़े सहारे की जरूरत है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में प्रियंका गांधी की करीब १०० रैलियां आयोजित कराने की योजना बनाई है। अभी तक प्रियंका प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गई है। हालांकि वह ४ अप्रैल को अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनके नामांकन में शामिल होने के लिए केलरल वायनाड गई थीं। प्रियंका कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रैलियां कर सकती हैं। कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयां वोटरों को लुभाने के लिए अपने राज्य में उनकी रैली की मांग कर रहे हैं। एक कांग्रेसी नेता ने बताया, प्रियंका गांधी को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपने क्षेत्र में उनकी रैली आयोजित करवाना चाहते हैं। चूंकि, उनका सभी जगहों पर जाना संभव नहीं है। इसलिए उन सीटों की लिस्ट बनाई जा रही है, जहां उनके जाने से नतीजे हमारे पक्ष में आ जाने की उम्मीद है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की ही तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रियंका की महिलाओं और छात्रों के साथ संवाद करवाने योजना बना रही है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि देश के उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है, जहां प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। एक कांग्रेसी नेता ने बताया, जमीनी रिपोर्ट के आधार पर लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें उन सीटों पर फोकस किया गया है, जहां कांग्रेसी उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत है और उन्हें थोड़े सहारे की जरूरत है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में प्रियंका गांधी की करीब १०० रैलियां आयोजित कराने की योजना बनाई है। अभी तक प्रियंका प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गई है। हालांकि वह ४ अप्रैल को अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनके नामांकन में शामिल होने के लिए केलरल वायनाड गई थीं। फिलहाल, कांग्रेस महासचिव का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है और वह अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो कर रही हैं। कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, जैसे ही यह काम पूरा होता है प्रियंका अगले हफ्ते से उनके पक्ष में भी ताबड़तोड़ रैलियां करना शुरू कर देंगी।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH